



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

02 चैत्र 1944 (श10)

(सं० पटना 119) पटना, बुधवार, 23 मार्च 2022

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

21 मार्च 2022

सं० 02/एम0एम0-(बा0)-30/21-1303/एम0—बालू के निक्षेपों के सही निर्धारण एवं मॉनसून के उपरांत बालू की मात्रा के आकलन हेतु वैज्ञानिक तरीके से नदियों का पुनर्भरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालू खनन के संबंध में निर्गत प्रवर्तन और निगरानी मार्गदर्शिका-2020 (EMGSM-2020) में भी नदियों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्भरण अध्ययन कराया जाना अनिवार्य है।

2. बालू खनन के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त के अनुसार पूर्व में पुनर्भरण अध्ययन बालू बंदोबस्तधारी द्वारा कराया जाता था। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बालूघाटों का संचालन बिहार राज्य खनन निगम द्वारा कराया जा रहा है तथा बालूघाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति भी निगम के पक्ष में हस्तांतरित है। इसलिए राज्य के प्रमुख नदियों का पुनर्भरण अध्ययन विभाग द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

3. प्रवर्तन और निगरानी मार्गदर्शिका-2020 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनर्भरण अध्ययन विशिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से आधुनिक तकनीक से ही कराया जा सकता है। मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान के चयन में विशिष्टता, गुणवत्ता एवं अनुभव के आलोक में सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि० के माध्यम से पुनर्भरण अध्ययन संचालित करने हेतु प्रथम वर्ष के लिए ₹1,97,55,000/- (18% वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) एवं द्वितीय वर्ष के लिए ₹1,54,75,350/- (18% वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) का शुल्क देय है।

4. अतः पंचांग वर्ष 2022 में राज्यान्तर्गत 04 प्रमुख नदियाँ यथा—सोन, कियूल, फल्गू एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) नामांकन के आधार पर सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि० (CMPDI) से ₹2,33,10,900/- (दो करोड़ तैंतीस लाख दस हजार नौ सौ रूपया) पर कराने की स्वीकृति दी जाती है।

5. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 119-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>